नमामि गंगे मिशन का आगे बढ़ता सफर

–संजय श्रीवास्तव

गंगा नदी में पिछले तीन साल से कई स्तर और कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें नदी की सफाई से लेकर जैव विविधता संरक्षण से घाटों को बेहतर करने के अभियान शामिल हैं। इस बीच पांच राज्यों में गंगा के किनारे के हजारों गांव खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिए गए हैं तो नदी के किनारे के इलाकों में वन विकसित करने के काम चल रहे हैं; ये सारे ही काम अगले कुछ बरसों में गंगा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी को बचाने का एक एकीकृत प्रयास है। इसके अंतर्गत व्यापक तरीके से गंगा की सफाई करने को प्रमुखता दी गई है।

नमामि गंगे परियोजना पर काम जारी है। पवित्र, पुण्यसलिला गंगा नदी की सफाई का महाअभियान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक बड़े सीवेज परिशोधन संयंत्र की आधारशिला रखकर लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गंगा नदी में पिछले तीन साल से कई स्तर और कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें नदी की सफाई से लेकर जैव विविधता संरक्षण से घाटों को बेहतर करने के अभियान शामिल हैं। इस बीच पांच राज्यों में गंगा के किनारे के हजारों गांव खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिए गए हैं तो नदी के किनारे के इलाकों में वन विकसित करने के काम चल रहे हैं; ये सारे ही काम अगले कुछ बरसों में गंगा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी को बचाने का एक एकीकृत प्रयास है। इसके अंतर्गत व्यापक तरीके से गंगा की सफाई करने को प्रमुखता दी गई है।

नमामि गंगे मिशन के तहत कुल 160 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसकी लागत 12,500 करोड़ रुपये है जबकि गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपये की परियोजना तय की गई थी। इसके तहत रिवर फ्रंट का विकास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, घाट और शवदाहगृह बनाना शामिल है। अभी तक एक चौथाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी को जल संसाधन और नमामि गंगे का भी प्रभार मिलने से काम में आ रही अड़चनें तो दूर होनी चाहिए बल्कि अंतर–मंत्रालयीय तालमेल में तेजी आ जानी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने जल मंत्रालय का पदभार संभालते ही कहा कि गंगा का काम सिर्फ एक विभाग का नहीं है, यह कई मंत्रालयों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वह टास्क फोर्स बनाकर इससे निपटने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि किसी न किसी रूप में परियोजना से अवगत होने के कारण उन्हें इसकी बारीकियों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

प्रधानमंत्री का बड़ा कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर, 2017 को वाराणसी के रमना में 50 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) की आधारशिला रखी। यह संयंत्र हाइब्रिड एन्यूटी– मॉडल पर आधारित है। सीवेज क्षेत्र में पहली बार हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निर्मल गंगा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। 153.16 करोड़ रुपये की लागत वाले इस संयंत्र के निर्माण, परिचालन व रखरखाव का कार्य एक कॉन्सोर्टियम को दिया गया है जिसकी अगुवायी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी कर रही है। भारत सरकार

नदी सफाई की मिसाल टेम्स नदी

टेम्स नदी कभी दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग हुआ करती थी। लंदन की आबादी बढ़ने के साथ ही टेम्स नदी में भी प्रदूषण बढ़ता गया। सन 1850 तक लंदन की टेम्स नदी का हाल दिल्ली की यमुना नदी से भी बदतर था। गंदगी की वजह से लंदन में हैजा फैल गया। टेम्स नदी की सफाई के लिए हालांकि समय–समय पर लंदन में कई जन–अभियान शुरू किए गए। इस खतरे को देखते हुए 1958 में संसद ने एक मॉडर्न सीवेज सिस्टम की योजना बनाई। इस योजना के चीफ इंजीनियर जोसेफ बेजेलगेट थे। उन्होंने काफी शोध के बाद पूरे लंदन शहर में जमीन के अंदर 134 किलोमीटर का एक सीवेज सिस्टम बनाया। साथ ही टेम्स नदी के साथ–साथ सड़क बनाई गई, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए। इस सीवेज सिस्टम में टेम्स का पानी ट्रीटमेंट के बाद लोगों के घरों में जाता है और लोगों के घरों में उपयोग किए गए जल–मल को ट्रीटमेंट के बाद टेम्स में छोड़ा जाता है। लंदन के इस सीवेज सिस्टम को बने हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं। लंदन शहर की जनसंख्या आज कई सौ गुना ज्यादा हो गई है, लेकिन आज भी लंदन का सीवेज सिस्टम दुरुस्त है। योजना का मतलब यही होता है कि उसे भविष्य को समझते हुए बनाया जाए। हमारे यहां सब उल्टा हो रहा है। अंग्रेजों का शासन–तंत्र मौजूद है, लेकिन दूरदर्शिता नहीं है। टेम्स नदी को लेकर वहां की सरकार भी कितनी ज्यादा गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1950 में नया जलशोधन यंत्र लगाया गया और 1960 में नया कानून बनाकर वैसी कम्पनियों को बंद कर दिया गया जो गंदा पानी टेम्स में छोड़ रहे थे।

दूसरी तरफ 2000 में शुरू हुआ टेम्स रिवर क्लीनअप अभियान टेम्स के लिए वरदान साबित हुआ। इस अभियान के तहत साल में तय एक दिन लंदन शहर में जहां–जहां से टेम्स नदी गुजरती है, हर जगह लोग एकत्र होकर नदी की सफाई करते हैं। पिछले कई सालों से टेम्स रिवर क्लीनअप अभियान निरंतर जारी है। इस अभियान की खास बात यह है कि सफाई के लिए टेम्स के तट पर पहुंचने वाले सभी लोग सफाई का सारा सामान अपने साथ लेकर आते हैं। और साल में तय उस दिन पूरी 346 किलोमीटर लंबी टेम्स नदी की सफाई की जाती है, ताकि किसी भी एक हिस्से में गंदगी रहने पर पूरी नदी फिर से प्रदूषित न हो जाए। ये वहां के लोगों के जज़्बे और इच्छाशक्ति का ही नतीजा है कि बहुत कम समय में ही अपने बल पर वहां के लोगों ने टेम्स को वापस उसके पुराने स्वरूप में लौटा दिया है।

द्वारा अनुमोदित हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत केंद्र सरकार इस परियोजना का 100 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। इस मॉडल के तहत एसटीपी का विकास, परिचालन और रखरखाव स्थानीय–स्तर पर बनाई गई एक स्पेशल पर्पज विह्कल (एसपीवी) करेगी। इस मॉडल के अनुसार लागत की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्माण के दौरान किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले 15 वर्षों के दौरान वार्षिक तौर पर किया जाएगा जिसमें परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) का खर्च भी शामिल होगा। इस मॉडल की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वार्षिक और परिचालन व रखरखाव (ओ एंड एम) के दोनों भुगतानों को एसटीपी के प्रदर्शन के साथ जोड़ा गया है। इससे संयंत्र का बेहतर प्रदर्शन, स्वामित्व और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

गंगा के किनारे के हजारों गांव खुले में शौच से मुक्त

पिछले महीने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पेयजल व स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि गंगा के किनारे के पांच राज्यों– उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 4460 से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। ये काम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। गंगा ग्राम विकसित करने की दिशा में पांच राज्यों– उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे बसी 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इन ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाने के लिए 578 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस धनराशि से 15 लाख 27 हजार 105 शौचालय बनाए जाने है। इनमें से आठ लाख 53 हजार 397 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं।

सीवर ट्रीटमेंट क्षमता वृद्धि

पांच राज्यों– उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 63 सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन के दौर में हैं। इन राज्यों में 12 नए सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट्स लांच कर दिए गए हैं। इनकी क्षमता को 1187.33 एमएलडी तक पहुंचाने के लिए काम जारी है।

जैव विविधता संरक्षण

गंगा की जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए कई जैव–विविधता संरक्षण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, इनमें जैव–विविधिकरण और गंगा पुनर्जीवन, गंगा नदी में मछली और मत्स्य संरक्षण, गंगा डाल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में जैव–विविधता धरोहर संरक्षण के पांच केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

वनारोपण

भारतीय वन्यजंतु संस्थान, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य रिसर्च संस्थान और पर्यावरण शिक्षा संस्थान के जरिए गंगा के किनारे के इलाकों में वनारोपण अभियान शुरू किया जा चुका है।

देहरादून के वन शोध केंद्र द्वारा तैयार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर पांच सालों के लिए गंगा के किनारों पर (2016–2021) 2300 करोड़ रुपये की लागत से वनारोपण चल रहा है। औषधीय पौधों के विकास की योजना उत्तराखंड के सात जिलों में चल रही है। जन भागीदारी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है और जनता का जुड़ाव भी बढ़ रहा है।

जन–जागरूकता

इसके लिए इवेंट्स, वर्कशाप, सेमिनार और कांफ्रेंस के जरिए जन–जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनियों, श्रमदान, स्वच्छता कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, पौधारोपण अभियान और टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं इसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के भी तमाम प्लेटफार्म्स का उपयोग हो रहा है।

नदियों के किनारों का विकास

नदी के किनारे को विकसित करने के लिए 28 परियोजनाओं, 182 घाटों और 118 श्मशान स्थलों की मरम्मत, आधुनिकीकरण तथा निर्माण की 33 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 11 स्थानों पर नदी की सतह और घाटों के आसपास सतह की सफाई और वहां से निकाले गए कचरे को नष्ट करने का काम जारी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में गंगा के किनारे बनने वाले 70 घाटों में 35 का निर्माण सिंचाई विभाग करेगा। नेशनल मिशन क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने पहले सभी 70 घाटों के निर्माण का जिम्मा निजी संस्था वेबकॉज को दिया था। प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में गंगा को साफ रखने के लिए नदी के किनारे कुल 70 शवदाह–स्नानगृह (घाट) बनाए जाने हैं। इसमें भी अब राज्य सरकार की भूमिका अहम हो गई है।

नदियों के सतह की सफाई

11 घाटों और नदियों की सतह पर इकट्ठा कूड़े का निस्तारण और सफाई– इस सफाई योजना के तहत पिछले वर्ष इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, वृन्दावन और पटना में ट्रेश स्कीमर से सफाई का कार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुरू किया गया था। इस दौरान टनों मात्रा में कचरा इकट्ठा कर निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। आने वाले समय में अन्य चयनित शहरों में भी ट्रेश स्कीमर से नदी की सतह की सफाई शुरू की जाएगी।

सात आईआईटी से मदद

सात आईआईटी (कानपुर, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, खड़गपुर, गुवाहाटी और रुड़की) के कंसोर्टियम द्वारा गंगा के लिए एक व्यापक नदी घाटी प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। यह योजना गंगा की पारिस्थितिकी के समग्र पुनरुद्धार तथा इसके पारिस्थितिकीय विज्ञान स्वास्थ्य के सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने के उद्देश्यों के साथ तैयार की जा रही है जिसमें नदी घाटी में प्रतिस्पर्धी जल प्रयोग के मुद्दे पर पर्याप्त विचार किया गया है। इसकी समग्रता को चार पारिभाषित अवधारणाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है– "अविरल धारा' (निरंतर प्रवाह), "निर्मल धारा" (प्रदूषणरहित प्रवाह), भू–पारिस्थितिकी संस्था और पारिस्थितिकी संस्था।

तब अंग्रेज ले जाते थे गंगा का पानी

मिथक कथाओं में, वेद, पुराण, रामायण महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी–बूटियों से मिलती–मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है, जिसे हम अभी नहीं समझ पाए हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे, तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब सवा सौ साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डाक्टर एमई हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया।

वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं. ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं।

प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों पर रोक

गंगा किनारे स्थित 760 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है जिनसे निकलने वाले कचरे से नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ऐसी 562 इकाइयों में कचरा निगरानी यंत्र लगाए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाली 135 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शेष इकाइयों को अपने यहां कचरा निगरानी व्यवस्था को तय समय में लगाने को कहा गया है। गंगा को प्रदूषण–मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने कानपुर तथा कन्नौज जनपदों में चल रही चमड़ा उद्योग इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं।

अन्य देशों से भी सहयोग

गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए दुनियाभर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जानकारी और संसाधन प्राप्त करने के प्रयासों के अलावा उन देशों से भी सहयोग लेने में संकोच नहीं किया जा रहा है जिन्हें नदी की सफाई में विशेषज्ञता हासिल है। आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फिनलैंड और इजराइल जैसे देशों ने गंगा संरक्षण में सहयोग देने की इच्छा जताई है।

पहली बार स्थानीय निकायों का सहयोग

स्वच्छ गंगा अभियान में पहली बार स्थानीय निकायों का

सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। विशेषज्ञ इस पहल को अच्छा कदम बताते हैं और मानते हैं कि यह कार्ययोजना इस बार अवश्य सफल होगी। पहले केंद्र गंगा सफाई के लिए राज्य सरकारों को धनराशि देता था। इस बार यह राशि राज्य सरकारों की बजाय सीधे स्थानीय निकायों को दी जा रही है। इससे न केवल उनकी भागीदारी बढ़ी है बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। इसके अच्छे नतीजे भी आने लगे हैं। स्थानीय–स्तर पर गंगा संरक्षण कार्यबल का गठन एक ठोस कदम की शुरुआत है। इससे गांव के युवा को जहां रोजगार मिलेगा वहीं ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि ये भी देखना होगा कि नगरपालिकाएं सीवेज ट्रीटमेंट संयत्रों को चलाने में पूरी रुचि लें।

राज्य सरकारों का सहयोग जरूरी

नमामि गंगे की सफलता के लिए राज्य सरकारों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने पर काम में जरूर तेजी आई। हालांकि काम इतना आसान नहीं क्योंकि गोमती आमतौर पर गंदे नाले में तब्दील हो गई लगती है। पीलीभीत के गोमद ताल, माधवटांडा से लेकर सीतापुर, हरदोई, लखनऊ बहराइच, जौनपुर व बनारस से पहले कैथीधार पर जाकर गंगा से मिलने वाली गोमती अपने 325 किलोमीटर लम्बे मार्ग में कहीं भी साफ नहीं।

उत्तर भारत की नदियां

यमुना में मिलने वाली हिंडन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिलों से गुजरती हुई, दिल्ली के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। हिंडन की लम्बाई करीब 400 किलोमीटर है। इसका जलागम क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। हिंडन एक बड़े जलागम क्षेत्र और घनी आबादी वाले औद्योगिक नगरों को जल निकास व्यवस्था प्रदान करती है। पिछले कुछ बरसों से प्रदूषण के कारण ये नदी भी चर्चा में है। इसके अलावा उत्तर भारत में कहीं भी चले जाइए। आमतौर पर बरसात के सीजन के अलावा सभी छोटी नदियां नाले में बदल गई हैं तो कहीं पतली धारा में। माना जाता है कि उनकी इस हालत के लिए कहीं बांध और बैराज जिम्मेदार हैं तो कहीं बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदूषण।

नर्मदा की हालत

गंगा के बाद देश की दूसरी पवित्र नदी नर्मदा है। उसे उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह गंगा को। अमरकंटक से शुरू होकर विंध्य व सतपुड़ा की पहाड़ियों से होते हुए अरब सागर में मिलने वाली नर्मदा का कुल 1,289 किमी की यात्रा में केवल दोहन हुआ है जिसने इस पवित्र और निर्मल नदी की दुर्दशा कर दी है। नर्मदा नदी के तट पर बसे नगरों और बड़े गांवों के पास के लगभग 100 नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं। शहर का गंदा पानी नदी में मिलता है। अब तो उद्गम इलाके अमरकंटक में भी नर्मदा प्रदूषित दिखती है। कई स्थानों पर गंदगी खतरनाक स्तर को पार कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार नर्मदा को साफ करने के अभियान में लगी हुई है। बैतूल जिले के मुलताई से निकल सूरत तक जाकर अरब सागर में मिलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती नदी का हाल भी अच्छा नहीं। तमसा बहुत पहले विलुप्त हो चुकी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ईमेल : sanjayratan@gmail.com

ग्यारह साल की बच्ची ने अपने जेब खर्च से बनवाया शौचालय

मोंद्रिता चटर्जी जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल में पढ़ने वाली एक ग्यारह साल की बच्ची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण में उसने सुना कि उसकी उम्र की लड़कियां बस इसलिए स्कूल जाना बंद कर रही हैं कि स्कूल में शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। यह सुनकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ और वह बहुत ही दुखी हुई। उसने उसी दिन से प्रण किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी उम्र की हर लड़की के लिए वह एक मिसाल बने।

अपने जेब खर्च के थोड़े–थोड़े पैसे जमा कर उसने कुल 24,000 रुपये जमा किए, जिससे उसने बाद में जमशेदपुर ब्लॉक की छोटा गोविन्दपुर पंचायत के केंद्रधि गांव में दो शौचालय बनवाए। मोंद्रिता की यह पहल आज गांव एवं स्कूल के सभी लोगों की जुबान पर है। इस स्वच्छ प्रयास को सलाम, जिसके कारण इस गांव की तस्वीर अब बदलती नजर आती है। मोंद्रिता हर सप्ताह गांव में जाकर स्वच्छता संबंधित जागरुकता बढ़ाने का कार्य करती है।

मोंद्रिता के इस अथक प्रयास के कारण राज्य सरकार

द्वारा उसे पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान में जमशेदपुर के उपायुक्त द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई है और उसे अपने क्षेत्र में स्वच्छता दूत भी बनाया गया है। ❑